दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 08 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 339

महत्वपूर्ण एवं खास

आईएसआई के निर्देश पर 200 आतंकवादी सक्रीय

नई दिल्ली (आरएनएस)। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंक का रहनुमा पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर हसरते फिर से उबाल मारने लगी है। इसे ये भ्रम है कि तालिबान की मदद से वो जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे सकता है। अब भारतीय सिक्योरिटी सर्विस सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान की आईएसआई पहले के मुकाबले जम्मू-कश्मीर में अधिक आक्रामक रणनीति पर नजर गड़ाए हुए है। सूत्रों के अनुसार तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले ही पाकिस्तान इस रणनीति पर काम कर रहा है। जिसके तहत आईएसआई पिछले दो महीनों से अपने संरक्षित आतंकवादी संगठनों लश्कर, जेईएम और अल-बद्र को जम्मू कश्मीर में भेज रहा है। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने टीओआई को बताया कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में लगभग 200 आतंकवादी सक्रिय हैं।

कार-ट्रक में जोरदर भिड़ंत, पति-पत्नी सहित 5 की मौत

गाजियाबाद (आरएनएस)। हरिद्वार से बीती देर रात गाजियाबाद लौट रहे एक दो परिवारों के पांच लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा मसूरी और भोजपुर कोतवाली क्षेत्र की सीमा के पास कलछीना गांव के सामने सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे का है। हादसे में घायल दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ। हरिद्वार से गाजियाबाद आने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे पर गांव कलछीना के निकट ट्रक से कार टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार 7 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। कार में 7 लोग सवार थे जिसमें 3 बच्चे और 4 बड़े लोग शामिल थे। कार में 2 परिवार के लोग सवार थे। दोनों परिवार में दोनों पति-पत्नी सहित 5 की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 बड़े लोग और एक बच्चा शामिल है। जबकि 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में आशीष पुत्र बीपी सिन्हा (उम्र 35 वर्ष), शिल्पी पत्नी आशीष (उम्र 30 वर्ष), देव पुत्र आशीष (1 वर्ष) निवासी लखनऊ के अलावा सोनू, परी पुत्री सोनू की भी मृत्यु हो गई।

चीन ने किया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन-502 का प्रक्षेपण

ताइयुआन। चीन ने उत्तरी प्रांत शांक्सी के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से आज नये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'गाओफेन-502' का प्रक्षेपण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गाओफेन-502 उपग्रह का प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार मंगलवार 11ः01 बजे किया गया। उन्होंने बताया कि उपग्रह को लॉन्ग मार्च-4सी रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 387वां उड़ान मिशन था। गौरतलब है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैर सैन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, जैसे पर्यावरण की निगरानी, मौसम विज्ञान अध्ययन, नक्शे का निर्माण आदि।

तूफान इडा के कारण अमेरिका के लुइसियाना में 13 लोगों की मौत

ह्यूस्टन। ट्रैकिंग वेबसाइट पावर आउटेज डॉट यूएस के अनुसार, तटीय राज्य में श्रेणी 4 के तूफान के रूप में इडा के लैंडफॉल के एक सप्ताह बाद, दक्षिणी अमेरिकी राज्य लुइसियाना में सोमवार तक तेरह लोग मारे गए हैं और लगभग 500,000 के घरों और व्यवसायों में बिजली आपूर्ति रुक गई है। राज्य के सबसे बड़े शहर न्यू ऑरलियन्स के अधिकांश निवासियों के पास बुधवार तक बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके इस महीने के अंत तक अंधेरे में रह सकते हैं। इडा ने 22,000 से अधिक बिजली के खंभे, 26,000 स्पैन तार और 5,261 ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 902,000 ग्राहक बिजली से वंचित है। एंटरगी ने सप्ताहांत के दौरान कहा कि करीब 24,000 लोग बिजली बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। एक अन्य विकास में, लुइसियाना स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को राज्य की 13 वीं इडा से संबंधित मौत की पुष्टि की। ऑरलियन्स पैरिश में 74 वर्षीय एक व्यक्ति की बिजली गुल होने के दौरान गर्मी से मौत हो गई।

ऑस्ट्रेलिया ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अकादमिक चेयर की नियुक्ति हेतु सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली (आरएनएस)। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अकादमिक चेयर की नियुक्ति के लिए एनआईसीएम वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल मोड में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश एवं विदेश मंत्री डैन तेहान एमपी की उपस्थिति में, आयुष मंत्रालय के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के कुलपति एवं अध्यक्ष प्रोफेसर बार्नी ग्लोवर ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

नया अकादमिक चेयर हर्बल औषधि तथा योग सहित, आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक और संबद्ध अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने के साथ-साथ शैक्षिक मानदंडों और

अल्पकालिक/मध्यकालिक पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक मार्गनिर्देशों की रूपरेखा तैयार करेगा। यह चेयर आयुर्वेद पर कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन भी आयोजित करेगा, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेद प्रणालियों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग पर जोर देगा, आयुर्वेद पर अकादमिक और अनुसंधान पाठ्यक्रमों में उनकी ताकत और कमी की पहचान करेगा, अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित छात्रों को ट्यूटोरियल प्रदान करेगा। इसके अलावा, भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा में अच्छी तरह से साक्ष्य आधारित आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए, मजबूत ऑस्ट्रेलियाई नियामक ढांचे के भीतर आयुर्वेद से संबंधित अनुसंधान और नीति विकास शिक्षण में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा।

वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के प्रति कुलपति प्रो. लिंडा टेलर और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के कुलपति एवं अध्यक्ष प्रो. बार्नी ग्लोवर ने स्वागत भाषण में कहा कि इस पहल से दोनों देशों को काफी फायदा होगा और अनुसंधान नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सामाजिक विकास में भी मदद मिलने के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अपने मंत्रिस्तरीय उद्घाटन संबोधन में, चेयर के बारे में एमओयू की आवश्यकता पर जोर दिया और आयुष मंत्रालय के सहयोग तथा समर्थन का आश्वासन दिया। यह आयुर्वेद अकादमिक चेयर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के वेस्ट मीड परिसर स्थित एनआईसीएम स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में स्थापित होगा, जिसका कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगा। इस अकादमिक चेयर की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषण किया जाएगा और 2022 के प्रारंभ में इसके शुरू होने का अनुमान है।

पुजारी नहीं हो सकता मंदिर का मालिक : सुप्रीम कोर्ट

» भू-राजस्व में देवता के नाम ही होगी सम्पत्ति

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने भू-राजस्व के रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या सम्पत्ति का मालिक नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है। मंदिर की सम्पत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता व एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि पुजारी के पास मंदिर या मंदिर की सम्पत्ति केवल प्रबंधन के लिए ही होती है। वह सिर्फ देवता की जगह पर उस मंदिर में काम करता है। चूंकि, देवता का नाम कानून में विधि सम्मत है इसलिए भू राजस्व के रिकॉर्ड में देवता के नाम ही मंदिर की सम्पत्ति रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही भू-राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दिए हैं।

किराएदार जैसा है पुजारी- कोर्ट ने कहा कि पुजारी उस जमीन की सिर्फ देखभाल करता है। वह सिर्फ एक किराएदार जैसा है। जो भी पुजारी होगा व मंदिर के देवताओं की देखभाल के साथ उससे जुड़ी जमीन पर खेती का काम भी करेगा।

बरकरार रखा मध्य प्रदेश का सर्कुलर- मध्य प्रदेश के 1959 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्कुलर को बरकरार रखा है। इस सर्कुलर में पुजारियों के नाम भू राजस्व के रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए गए थे, जिससे मंदिर की सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचे जाने से बचा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट में हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील से कहा है कि आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते न ही ऐसा ओदश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं।

दरअसल, टोक्यो ओलंपिक में महिला और पुरुष हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हॉकी को अधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिक दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी ने मांग की थी कि एथेलेटिक्स जैसे खेलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं और हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया था कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना तो जाता ही है, लेकिन उसे अभी तक आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। हॉकी भारत का गौरव है,जो अपनी पहचान खोता जा रहा है।

1928 से 1956 तक का समय भारतीय हॉकी के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। वैसे तो यह खेल लगभग सभी देशों में खेला जाता है, लेकिन 1928 में भारत हॉकी का विश्व विजेता बना था। वहीं इसके बाद हुए ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कई स्वर्ण पदक भी अपने नाम किए।

कृषि कानूनों-महंगाई पर अपने भी सरकार के खिलाफ

» भारतीय किसान संघ ने मांगी एमएसपी पर कानूनी गारंटी

» 5 सौ जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आज

» भारतीय मजदूर संघ कल देगा महंगाई के खिलाफ धरना

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब अपने भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों के खिलाफ बुधवार को देश के पांच सौ जिलों में प्रदर्शन की घोषणा की है। इसके अलावा संघ के ही दूसरे अनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने बृहस्पतिवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।

भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार की वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था महज एक धोखा है। किसानों को अब भी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। वर्तमान में महज कुछ फसलों का पचीस फीसदी हिस्सा ही एमएसपी के तहत खरीदा ज्यादा है। वह भी बस पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। बाकी के राज्यों के किसान सरकारी खरीद के लिए बस अपना पंजीयत ही कराते रह जाते हैं। एमएसपी की न तो गारंटी है न ही इसकेलिए ठोस कानून ही है। अगस्त महीने में संगठन के सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों की बैठक की थी। अब हमने बुधवार को देश भर के पांच सौ जिलों में सांकेतिक धरना देने और इन जिलों में डीएम को ज्ञापन देने का फैसला किया है। चौधरी ने कहा कि संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में है, मगर हमने इसमें पांच संशोधन सुझाए थे। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

देश में कोरोना मामलों से मिली राहत, 24 घंटे में 31,222 नए मामले, 290 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच राहत देता नजर आया। देश में पिछले 24 घंटे में 31,222 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कारण 290 मरीजों की मौत दर्ज की गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ो के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.30 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जबकि 290 मरीजों की और मौत के साथ देश में संक्रमण के कारण अब तक 4.40 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब देश में सक्रीय मरीज चार लाख से कम होकर 3,92,864 यानि 1.19 प्रतिशत तक आ गये है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए 42,903 मरीजों के बाद देश में अब तक

3,22,24,937 इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी रेट अब 97.48 प्रतिशत हो गई है।

केरल में भी नए केसों में गिरावट

मंत्रालय के अनुसार केरल, महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार तेज होने से लोगों की बॉडी में हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो रही है, जिससे संक्रमण की चपेट में लोग कम आ रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 6 सितंबर तक 53 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जबकि, सोमवार को 15 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है।

आधी से ज्यादा आबादी का टीकाकरण- मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस पर बीते 24 घंटों में भारत ने डबल अटैक किया है। यानि एक तरफ देश में 1.13 करोड़ लोगों को महाअभियान के तहत कोरोना वैक्सीन लगी है। कोरोना वायरस से जंग में देश ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब तक देश भर में 70 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। यही नहीं 60 करोड़ से आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंचने में महज 13 दिनों का ही वक्त लगा है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी और तब से अब तक इसकी स्पीड में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले 10 करोड़ टीके लगने में जहां 85 दिनों का वक्त लगा था। वहीं यह आंकड़ा 10 से 20 तक पहुंचने में 45 दिन ही लगे थे। उसके बाद से लगातार कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा देखने को मिला था। 20 से 30 करोड़ डोज 29 दिनों में और फिर अगले 34 दिनों में यह आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया था।

तीसरी लहर नहीं होगी घातक- कोरोना से जंग में सबसे अहम टीकाकरण को माना जा रहा है और भारत ने उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बीते 11 दिनों में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। इसके साथ ही अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब पहुंच चुका है।

भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ जांच से पहले मंजूरी जरुरी

» केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, केंद्र ने कथित भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कोई भी जांच करने से पहले पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य पूर्वानुमति लेने के लिए एसओपी जारी की है। बता दें कि जुलाई 2018 में 30 साल से अधिक पुराने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 में किया गया संशोधन एक पुलिस अधिकारी को अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच करने से रोकता है। संशोधन लागू होने के तीन साल से भी अधिक समय बाद पूर्व अनुमति की प्रक्रिया के एकसमान तथा प्रभावी क्रियान्वयन के मद्देनजर प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए ये एसओपी जारी की गई। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया कि इन एसओपी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की चरणबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। इसमें पूर्व अनुमति मांगने के लिए पुलिस अधिकारी के दर्जे का भी उल्लेख है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष को 75 करोड़ रुपये का योगदान दिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन खेल विभाग के राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत कोल इंडिया लिमिटेड एनएसडीएफ को 75 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करेगा। यह धनराशि कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में दी जा रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक और खेल विभाग के सचिव रवि मित्तल भी इस मौके पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल के ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कोल इंडिया द्वारा एनएसडीएफ में बहुमूल्य योगदान उचित समय पर आया है। उन्होंने पैरालंपिक में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 19 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी। कोल इंडिया की पहल की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि कोयले के खनन से अर्जित धन का एक हिस्सा हमारे खिलाड़ियों को हीरे के रूप में तराशने के काम आएगा, जिससे उन्हें पोडियम पर खड़े होने की सफलता मिलेगी। अनुराग

ठाकुर ने कहा कि इस कोष का उपयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के क्रम में सामान्य और विशिष्ट खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस कोष का उपयोग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विकास के लिए भी विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। पिछले कई वर्षों में, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों ने एनएसडीएफ में उदारतापूर्वक योगदान दिया है। ठाकुर ने कहा, एसएआई और एलएनआईपीई के तहत खेल अकादमियों को एथलीटों के लिए अधिक होस्टलों की आवश्यकता थी। खेल एथलीटों के तीन छात्रावासों के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के 75 करोड़ रुपये के योगदान से प्रशिक्षण में आसानी होगी और सुविधाओं में वृद्धि होगी। ठाकुर ने आगे कहा कि बैंगलोर व भोपाल की साई अकादमियों और एलएनआईपीई ग्वालियर में तीन होस्टलों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से खेल विभाग/एनएसडीएफ तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच संबंध मजबूत होंगे। मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारतीय खेल प्राधिकरण और कोल इंडिया लिमिटेड को देश में खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से एक खेल अकादमी की स्थापना करनी चाहिए। ठाकुर ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों, कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों से अपील की कि वे आगे आएं और अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में एनएसडीएफ में उदारतापूर्वक योगदान दें और भारत के खेल महाशक्ति बनने की इस यात्रा में हितधारक बनें। अपने संबोधन के दौरान निसिथ प्रमाणिक ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने सदैव ही भारत में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा दिया है। प्रमाणिक ने आश्वासन दिया कि सीआईएल द्वारा प्रदान की गई धनराशि का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा और परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। खेल सचिव रवि मित्तल ने कहा कि इन तीनों अकादमियों में छात्रावासों के निर्माण से इन तीनों ही स्थानों पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविर लगाना संभव हो सकेगा। उन्होंने कोल इंडिया से भविष्य में भी एनएसडीएफ में अपना बहुमूल्य योगदान जारी रखने का आग्रह किया। कोयला सचिव अनिल जैन ने कहा कि देश में खेलों के विकास में योगदान देना कोल इंडिया के लिए गर्व की बात है।